



PMMVY के कार्यान्वयन संबंधी चर्चाएँ

प्रलिस के लयः

[प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना](#), [अंतरराष्ट्रीय शरु संगठन](#), [जननी सुरक्षा योजना](#), [पोषण अभयान](#)

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनयन, 2013, भारत में महिलाओं के लय सामाजक सुरक्षा एवं मातृ स्वास्थय ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यो?

[राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनयन \(NFSA\), 2013](#) के तहत मातृत्व लाभ एक वधिक अधकार होने के बावजूद, [प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना \(PMMVY\)](#) के कार्यान्वयन में चुनौतयो बनी हुई हैं, जससे लाखो गर्भवती महिलाओं को उचित सहायता नहीं मल पा रही है ।

PMMVY और इससे संबंधत चर्चाएँ क्या हैं?

- **PMMVY:** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत वर्ष 2017 में शुरू की गई **केंद्र प्रायोजत योजना** है, जसके तहत पात्र गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान कया जाता है ।
- हालाँक, सरकारी कर्मचारी और इस तरह का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएँ इसकी पात्र नहीं हैं ।
- **उद्देश्य:** यह मातृ पोषण सुनश्चित करने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, वततीय स्थरिता का समर्थन करने तथा बालकियों के जन्म को प्रोत्साहित करने पर केंद्रत है ।
- **मुख्य वशेषताएँ:** इसके तहत मातृ स्वास्थय एवं पोषण को समर्थन देने के कर्म में **वततीय सहायता** प्रदान कया जाना शामिल है ।
 - इसके अंतगत **पहले बच्चे के लय** 5,000 रुपए प्रदान कये जाते हैं तथा [जननी सुरक्षा योजना \(JSY\)](#) के अंतगत अतरकित लाभ के तहत महिलाओं को कुल मलकर लगभग **6,000 रुपए** प्राप्त होते हैं ।
 - **दूसरा बच्चा (केवल लडकी होने पर):** लैगक समानता को बढ़ावा देने और कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करने के लय 6,000 रुपए दये जाते हैं ।
- **चर्चाएँ:**
 - **सीमति कवरेज:** यह योजना **NFSA, 2013 का उल्लंघन** है, जो सार्वभौमक मातृत्व लाभ को अनवार्य बनाता है, क्योक इसमें लाभ केवल **पहले दो बच्चों तक सीमति** है, तथा दूसरे बच्चे को केवल तभी शामिल कया जाता यदवह **लडकी** हो ।
 - **बजट में कटौती:** वर्ष 2023-24 में, **केंद्र सरकार** ने इस योजना के लय केवल 870 करोड रुपए आवंटत कये, जो 2019-20 में आवंटत राशा का केवल एक तह्राई है ।
 - **90% जन्मों को 6,000 रुपए प्रत जन्म** का लाभ प्रदान करने हेतु कम-से-कम **12,000 करोड रुपए** की आवश्यकता होगी ।
 - **अनुपयुक्त कार्यान्वयन:** योजना का प्रभावी कवरेज वर्ष 2019-20 में **36%** से घटकर वर्ष 2023-24 में केवल **9%** रह गया ।
 - **नौकरशाही और डजिटल बाधाएँ:** यह योजना **आधार-आधारत सत्यापन मुद्दों**, जटल आवेदन प्रक्रयोओं और लगातार सॉफ्टवेयर वफलताओं से ग्रस्त है, जससे **गरीब और डजिटल रूप से नरकषर महिलाओं** के लय लाभ प्राप्त करना मुशकल हो रहा है ।

नोट: राज्य-वशषित योजनाओं के परणाम PMMVY से बेहतर होते हैं । तमलनाडु (84%) और ओडशा (64%) ने PMMVY (<10%) की तुलना में अधिक कवरेज हासल कया है । वे कर्मश: प्रतबालक 18,000 रुपए और 10,000 रुपए का लाभ प्रदान करते हैं, जो PMMVY की अक्षमता को उजागर करता है ।

NFSA के अंतगत मातृत्व लाभ के प्रावधान क्या हैं?

- **NFSA 2013:** इसका उद्देश्य भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिये संवहनीय खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करखाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
 - यह अधिनियम कल्याण-आधारित से अधिकार-आधारित खाद्य सुरक्षा की ओर बदलाव का प्रतीक है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक संरचित और वधिक रूप से बाध्यकारी बन गई है।
- **NFSA, 2013 के अंतर्गत मातृत्व लाभ:** सभी गर्भवती महिलाएँ (औपचारिक क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर) मातृत्व लाभ के रूप में प्रतिबच्चा 6,000 रुपए पाने की हकदार हैं।
 - मातृत्व लाभ गर्भवती महिलाओं के लिये उचित पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और आराम सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण है।

नोट: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार, भारत में औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलाता है।

- विश्व स्तर पर, 51% देश कम-से-कम 14 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करते हैं, जो कअंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) मातृत्व संरक्षण सम्मेलन, 2000 द्वारा निर्धारित मानक है।

आगे की राह:

- **ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन:** पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लियेमान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना।
 - अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कम आय वाले श्रमिकों को लाभ प्रदान करना, क्योंकि उनमें से कई भुगतान मातृत्व अवकाश के दायरे से बाहर हैं।
 - NFSA के अनुसार सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान करना, न किइसे केवल पहले और दूसरे बच्चे तक सीमित रखना।
- **समग्र दृष्टिकोण:** व्यापक मातृ देखभाल प्रदान करने के लिये JSY, पोषण अभियान और राज्य मातृत्व योजनाओं (तमलिनाडु और ओडिशा जैसे राज्य मॉडल) के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित करना।
- **बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों के लिये नकद हस्तांतरण को निःशुल्क पोषण कटि, प्रसवपूर्व देखभाल और प्रसवोत्तर सहायता के साथ संयोजित करना।**
- **नगिरानी:** नधि उपयोग और लाभार्थी पहुँच का मूल्यांकन करने के लिये नियमित स्वतंत्र रूप से ऑडिट आयोजित करना।
- **डिजिटल बाधाएँ दूर करना:** आधार से संबंधित मुद्दों के कारण बहिष्कार को रोकने के लिये वैकल्पिक पहचान सत्यापन शुरू करना।
 - जन धन खातों के साथ एकीकरण करके तथा अनावश्यक नौकरशाही अनुमोदन को हटाकर, बिना किसी देरी के भुगतान जमा किया जाना सुनिश्चित करना।

?????? ???? ???? ???? ????:

प्रश्न: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से किस प्रकार वरिधाभासी है? इस योजना को NFSA के साथ संरेखित करने के उपाय सुझाएँ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये, विशेष रूप से वृद्धावस्था और मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ठोस और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल नीतियों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2020)